प्रमुख नदियों की सफाई के लिए कार्य-योजना

299. **श्री बरजिन्दर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की प्रमुख नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए भविष्य में कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य-योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) इसे कब से प्रारंभ करके, कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है तथा इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना चरण-I, गंगा कार्य योजना चरण-II तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का प्रतिपादन देश के 146 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्य शुरू करके 14 राज्यों में 22 प्रमुख नदियों में जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया गया है।

(ख) इन कार्य योजनाओं में सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, सीवेज अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन कार्य, अल्प लागत स्वच्छता, काष्ट आधारित उन्त शवदाहगृह, नदी तटाग्र विकास सुविधाएं, वनीकरण स्कीमें तथा जनभागीदारी एवं-जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) कार्य शुरू करने, पूरा करने की निर्धारित तिथियां तथा इन कार्य योजनाओं की अनुमोदित लागत निम्नलिखित है:

स्कीम	शुरू किए जाने की तिथि	पूरा किए जाने की तिथि	अनुमोदित लागत
गंगा कार्य योजना चरण-I	जून, 1985	मार्च, 1999	462.04
गंगा कार्य योजना चरण-II	अप्रैल, 1993	मार्च, 2001	1281.17
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	जुलाई, 1995	मार्च, 2005	772.08

Non Implementation of Environmental Management Laws

300. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sluggish approach of the implementing agencies like pollution boards are largely responsible for non-implementation of the existing laws on Environmental Management, as brought out during a seminar on Environmental Management held at Nagpur on 14th April, 1998; and

(b) if so, the details of the steps being taken to sensitise the concerned agencies/authorities towards protection of the environment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI) : (a) and (b) The State Pollution Control Boards (SPCBs) in the States and Pollution Committees (PCCs) in Union Territories are implementing the existing laws on environment. The measures being taken to sensitise and strengthen the regulatory agencies include:

(1) Increasing water cess rates for augmenting the resources of the State Boards;

(2) Strengthening of State Boards in terms of laboratory facilities;

(3) Providing training to the officials on different aspects relating to prevention and control of pollution;

(4) Strengthening of State Boards under various bilateral programmes;

(5) Financial assistance on specific programmes for abatement of pollution.

(6) State Pollution Control Boards viz. Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Karnataka are being strengthened under the world Bank aided projects, and

(7) Regular interaction is done with State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees for formulating programmes for prevention and control of pollution.

Yamuna Action Plan

301. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: